OCTOBER - NOVEMBER

VOL. 2 | ISSUE 06

Youth Voice

यंग इंडिया की आवाज़

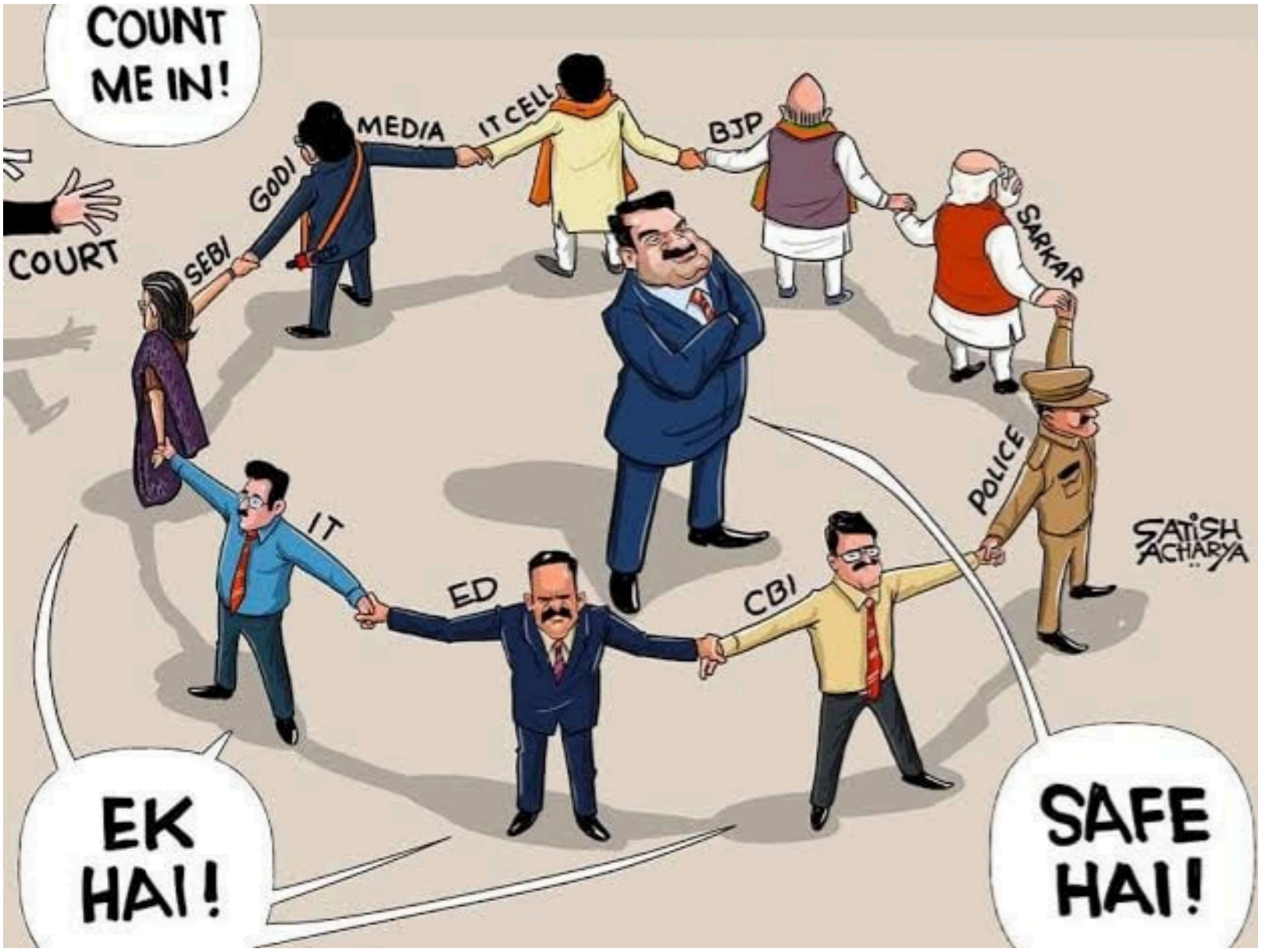

An Organ of RYA

YOUTH VOICE

New series
Vol. 2 Issue No. 06
OCTOBER - NOVEMBER
2024

CONTENTS

संपादकीय 1

बिहार में दलित उत्पीड़न: सामंती ताकतों का कहर और भाजपा-जदयू सरकार की विफलता 2

योगी शासित उत्तरप्रदेश महिलाओं व दलितों के लिए सुरक्षित नहीं, सड़कों पर निर्णायक प्रतिरोध की दरकार 3

R.G. Kar Movement Continues 5

झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा 6

बदलो बिहार न्याय यात्रा: युवा चेतना की नई लहर और बिहार के पुनर्निर्माण का आह्वान 7

Reports 8

Editor-in-chief
Niraj Kumar

Editor
Saba Parveen

Editorial Board
Sunil Maurya
Subhdeep
Montu Rajwar
Dnayneshwari
Watan

Art & Design
Neha
Akhilesh Raj

संपादकीय

अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय ने मोदी सरकार के सबसे दुलारे सेठ गौतम अडानी पर 2020 और 2024 के बीच, भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर से अधिक रिश्वत देने का आरोप लगाया. इस आरोप के बाद अमरीकी अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया.
भारत में तेजी से यह मांग उठने लगी कि भारतीय अदालत तुरंत इसपर संज्ञान ले और इसकी जाँच कराई जाय. मोदी सरकार पूरी तरह से अडानी के बचाव में उतर आई. यहाँ तक कि संसद के अन्दर अडानी पर बहस कराने की बात तो दूर अडानी का नाम को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया. आज देश भर में यह नारा गूँज रहा है “मोदी अडानी एक है! अडानी सेफ है!”

इस घटना से यह साफ़ हो गया है कि मोदी सरकार की प्राथमिकता में देश के नौजवान नहीं बल्कि अडानी जैसे पूंजीपति हैं जिनकी सेवा में पूरी सरकार लगी है. नौजवानों से धोखा और अडानी को मौका इस सरकार की नीति बन गई है.

अडानी की गिरफ़्तारी की मांग के बीच भाजपा-आरएसएस ने अपना पुराना तरकीब निकाला और देश में एक बार फिर से सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाना शुरू किया. जिसके लिए इन्होने उत्तरप्रदेश के संभल में स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद को चुना. जहाँ सर्वे ने नाम पर सांप्रदायिक उन्माद का माहौल बनाकर 5 मुस्लिम नौजवानों की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई. इस मामले को आतंकी साजिश बताने और पाकिस्तानी कनेक्शन ढूँढने में मोदी-योगी की पुलिस लगी हुई है.

मोदी सरकार जब-जब भी जनता के सवालों के निशाने पर होती है तब-तब सांप्रदायिक नफरत का माहौल बना कर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करती है.

आज देश के नौजवान ऐतिहासिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. देश मोदी सरकार के द्वारा ऐतिहासिक बेरोजगारी में धकेल दिया गया है. जो थोड़े बहुत नौकरियों की बहालियां निकलती भी हैं वह धांधली की चपेट में आ जाती है. और दूसरी तरफ अपने दुलारे पूंजीपतियों कि सेवा में पूरी सरकार,एजेंसियों, पुलिस फ़ौज को लगाई हुई है.

भाजपा के पूंजीपतियों से सेवा और विरोध की आवाज को सांप्रदायिक उन्माद के माहौल के नीचे गुम कर देने की सुपरिचित नीति के खिलाफ नौजवानों को संगठित होकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है.

बिहार में दलित उत्पीड़न: सामंती ताकतों का कहर और भाजपा-जदयू सरकार की विफलता

वतन कुमार

बिहार में दलित-पिछड़े समुदायों पर हो रहे अत्याचार, शोषण और हिंसा का क्रम बढ़ता जा रहा है और यह राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। गया, नवादा, सिवान अन्य जिलों में दलितों पर सामंती ताकतों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 2024 आम चुनाव के बाद राज्य में दलितों पर हिंसक हमलों की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दलित समुदाय राज्य सरकार सुरक्षा देने में विफल साबित हो रही है।

गया जिले के चिरैली गांव के संजय मांझी की घटना एक उदाहरण है जो यह दर्शाती है कि कैसे दलितों की भूमि और अधिकारों पर सामंती ताकतें हमला कर रही हैं। संजय मांझी पर किए गए हमले में उनके हाथ काट दिए गए, जब उन्होंने अपनी भूमि बचाने की कोशिश की। यह घटना उन बर्बर अत्याचारों में से एक है जिनका सामना दलितों को आज भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा बकरौर बोधगया में महादलित बस्ती पर हमला और खिजरसराय के ट्रैक्टर ड्राइवर सज्जन मांझी की मात्र 100 रुपए मजदूरी मांगने पर हत्या, यह दर्शाती हैं कि दलितों के खिलाफ हिंसा का पैमाना कितना व्यापक और निर्मम है। सज्जन मांझी की हत्या बिहार की कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है, विशेषकर तब जब यह घटना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के गृह क्षेत्र में हुई हो और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी तक नहीं की। यह प्रशासनिक विफलता और सरकारी उदासीनता का प्रतीक है।

बिहार में दलित पुरुषों के साथ-साथ दलित महिलाओं और बच्चियों को भी हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। शेरघाटी में मांझी परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं राज्य की सामंती ताकतों के जघन्य स्वरूप को उजागर करती हैं। इसी प्रकार बोधगया और इमामगंज में दलित लड़कियों के साथ हुई बलात्कार की घटनाएं दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की भयावहता को दर्शाती हैं। भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेता पर भी बलात्कार के आरोपों ने यह साबित किया है कि इस हिंसा में न केवल सामंती ताकतें शामिल हैं बल्कि भाजपा से जुड़े लोग भी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

बिहार में दलितों के उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण भू-माफियाओं द्वारा जमीनों पर कब्जे की होड़ है। नवादा जिले में 32 दलित परिवारों के घरों को जलाकर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। भूमि के अधिकार से वंचित करना दलितों के अस्तित्व पर सीधा हमला है। यह केवल जातीय उत्पीड़न का मामला नहीं है बल्कि इसके पीछे दलितों की जमीन हड़पने का एक सुव्यवस्थित प्रयास है, जिसमें भू माफियाओं के साथ-साथ राजनीतिक ताकतें भी शामिल हैं।

सरकार की ओर से भूमि सुधार या दलितों को जमीन का अधिकार देने की कोई ठोस योजना नहीं होने से, सामंती ताकतों को दलितों की जमीन हड़पने का खुला मौका मिल रहा है। यह स्थिति राज्य की जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार की असफलता को दर्शाती है, जो न केवल दलितों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है बल्कि उनके उत्पीड़न पर चुप्पी साध अपराधियों को मौन समर्थन दे रही है। दलितों के खिलाफ हिंसा और उनकी हत्या की घटनाओं में से कई बार उन पर अत्याचार तब होते हैं जब वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अरवल में भाकपा माले (लिबरेशन) के नेता सुनील चंद्रवंशी की हत्या इसका एक प्रमुख उदाहरण है। सुनील चंद्रवंशी ने गरीबों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, और इसी संघर्ष के प्रतिशोध में उनकी हत्या कर दी गई। सिवान में शिक्षक भरत मांझी की केवल मूंछ रखने पर हत्या की घटना यह दर्शाती है कि कैसे दलितों की पहचान पर हमला हो रहा है।इन घटनाओं के बावजूद, राज्य सरकार ने इन मामलों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन की लापरवाही और राजनीतिक तंत्र की उदासीनता इन घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर राज्य सरकार और प्रशासन का मौन रहना यह स्पष्ट करता है कि उनके बीच एक गहरा सांठगांठ है, जो सामंती ताकतों को प्रोत्साहित करता है।

बिहार में बढ़ते दलित उत्पीड़न का सीधा जिम्मेदार राज्य की भाजपा-जदयू सरकार है। क्योंकि सरकार न केवल इन घटनाओं को रोकने में विफल रही है बल्कि कई बार सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े लोग ही इन अत्याचारों में शामिल पाए गए हैं। सरकार का दलितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम न उठाना इस बात का संकेत है कि उनके लिए दलितों के मुद्दे प्राथमिकता में नहीं हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई घोषणाएं तो कीं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव नहीं दिखा। कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, और सामंती ताकतें दलितों के खिलाफ अपनी हिंसक गतिविधियों को खुली छूट के साथ अंजाम दे रही हैं।

दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाकर दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सामंती ताकतों और उनके सहयोगी भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी ताकि दलितों को न्याय मिल सके।

भारत के संविधान ने दलितों को समानता और न्याय का अधिकार दिया है लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक विफलताओं के चलते यह अधिकार केवल कागजी बनकर रह गए हैं। यह समय है कि दलितों के प्रति किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संघर्ष तेज की जाए.

योगी शासित उत्तरप्रदेश महिलाओं व दलितों के लिए सुरक्षित नहीं, सड़कों पर निर्णायक प्रतिरोध की दरकार

सुनील मौर्या

उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ती हिंसा और बलात्कार की घटनाएं आए दिन अखबारों में छपती है जो आंकड़े में भी साफ-साफ दिखाई देती है. राष्ट्रीय महिला आयोग के 2023 के जारी आंकड़ों के मुताबिक भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था. 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कुल 28,811 शिकायतें मिलीं थी जिसमें यूपी में करीब 16,109 यानी 55 प्रतिशत शिकायतें अकेले उत्तर प्रदेश से मिलीं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, आईपीसी और विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत महिलाओं के खिलाफ दर्ज मामलों में सबसे ज्यादा 65,743 की संख्या के साथ फिर से सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद महाराष्ट्र 45,331 मामले, राजस्थान 45,058 मामलों के साथ है. 2021 में, यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 56,083 मामले दर्ज किए गए.

वैसे तो उत्तर प्रदेश में कानून के नाम पर आतंक का राज चल रहा है विपक्ष की हर आवाज पर बुलडोजर चलाया जा रहा है लेकिन इसी दौरान पूरे प्रदेश से आई हजारों महिलाएं लखनऊ की सड़कों पर बलात्कार और हत्या के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ऐपवा की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा अधिकारी ने बताया कि महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश शर्मनाक ढंग से पहले नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की लगभग प्रत्येक जिले में महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, अपहरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं में पीड़ित महिलाओं और उनके परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा हे। आमतौर पर पुलिस थानों में महिला हिंसा की घटनाओं में एफआईआर तक दर्ज न की जा रही है बल्कि कई घटनाओं में तो पुलिस का रवैया पीड़िता के प्रति असंवेदनशील रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की कितनी ही बातें कर लें लेकिन महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं यह बता रही हैं की यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है।

संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ यूपी में बुल्डोजर से न्याय करने के लिए जाने जा रहे हैं, ठोक दो की राजनीति में विश्वास करते हैं. लेकिन आज तक मुख्यमंत्री यौन उत्पीड़न के आरोपी यूपी से सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ लिए कोई बयान तक नहीं दे सके और न ही आईआईटी बीएचयू के बलात्कारियों को जब हाल में रिहा किया गया। उनका स्वागत किया गया तब भी मुख्यमंत्री की खामोशी यह दर्शाती है कि सांसद, मंत्री और रसूखदार लोग अगर यौन शोषण, बलात्कार के आरोपी होंगे तो योगी सरकार का संरक्षण मिलेगा और बुल्डोजर एवं 'ठोक दो' की राजनीति आम जनता के लिए है.

ऐपवा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने बताया कि योगी राज में महिलाएं अपने ऊपर हर प्रकार की हिंसा झेल रही हैं। सरकार स्मार्ट परियोजनाओं के कारण गरीब महिलाओं और उनके परिवारों को शोषण और दमन झेलना पड़ रहा है; यहां तक की पीने के साफ पानी के लिए भी महिलाओं को आज भी कई किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। बढ़ती महंगाई से गरीब महिलाएं प्राइवेट लोन लेने के लिए मजबूर कर दी जा रही हैं और कर्ज न चुकाने पर उनका परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। महिलाओं के लिए स्थाई रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं हैं जिससे वह अपनी जिंदगी को सम्मानजनक तरीके से जी सके। योगी सरकार की उत्तर प्रदेश में नफ़रत और बुल्डोजर की राजनीति ने आग लगा दी है। बहराइच में एक युवक की हत्या और भीड़ द्वारा आगजनी और निर्दोष महिलाओं और बच्चों का पलायन इसका ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में निर्मम हत्या व बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं. अल्पसंख्यकों पर साजिश के तहत दमन ढाया जा रहा है. उपचुनाव में योगी सरकार व भाजपा को हराकर इसका बदला लेने के मूड में है.

देशभर में दलितों के खिलाफ अपराध की घटनाएँ बढ़ती जा रही है. साल 2018 से 2020 यानी तीन वर्षों में 1,39,045 मामले दर्ज किए गए हैं। तीन सालों में यूपी में 36,467, बिहार 20,973, राजस्थान 18,418 और मध्य प्रदेश में 16,952 दलितों पर जुल्म हुए। ये आंकड़े 2018 से 2020 के हैं। हालांकि, मंत्री द्वारा 2021 और 2022 के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

पूर्वांचल समेत पूरा प्रदेश जघन्य अपराधों के साए में है। हत्या, बलात्कार, लूट के मामले में असीम वृद्धि हुई है। ऐसा लगता है कि दलितों-पिछड़ों के खिलाफ दुर्भावना के तहत प्रदेश की सामंती ताकतें व पुलिस ने साझा अभियान छेड़ रखा है। हम आए दिन फर्जी एनकाउंटर के माध्यम पिछड़े-दलित-मुस्लिम युवकों की हत्या व अंग-भंग की घटनाऐं देख रहें हैं।

हत्याओं और बलात्कार के इस नृशंस राज में रायबरेली में एक दलित शिक्षक के पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या करने का प्रकरण सामने आता है। यह मामला भी अपने पूरे घटनाक्रम में अपराधियों के बुलन्द हौसले और कानून व्यवस्था के इकबाल के खात्मे की शिनाख़्त करता है।

उसी तरह से मिर्जापुर में गत 22 अक्टूबर को दबंगों ने जमीन विवाद में दलित समुदाय के राम अचल(70) के घर पर घातक हथियारों से लैस होकर धावा बोला और उनकी हत्या कर दी। हमले में परिवार की छह महिलाओं सहित नौ व्यक्तियों के सर फटे। गंभीर रुप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर बोलेरो, बाइक और ट्रैक्टर पर सवार होकर आए थे।वाम पार्टी से जुड़ी मजदूर नेता जीरा भारती ने बताया कि दलित परिवार चार दशकों से भी ज्यादा समय से ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन पर निवास करने के अलावा उसे जोत-बो रहा था। बीच में वाराणसी के रहने वाले एक व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके उसका पट्टा करा लिया और बाद में मिर्जापुर निवासी राजीव गुप्ता को बैनामा कर दिया। इसके खिलाफ दलित परिवार ने न्यायालय में मुकदमा कर रखा था। हाल ही में सिविल कोर्ट से दलित परिवार के पक्ष में आदेश हुआ था। खतौनी में भी दलित राम अचल का ही नाम मौजूद है। हमले की घटना से एक दिन पहले (21 अक्टूबर को) दलित परिवार ने आलू बोने के लिए खेतों की जुताई की थी। मृतक के पुत्र ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ हमलावरों को गिरफ्तार किया है।
जीरा भारती कहती हैं कि योगी सरकार में दबंगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दलितों पर हमले और हिंसा की घटनाएं खूब हो रही हैं। दबंगों को मिल रहे संरक्षण के चलते ही उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न की घटनाओं में टॉप पर है। बुल्डोजर प्रेमी मुख्यमंत्री योगी के शासन में दलितों-गरीबों की बेदखली हो रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है।गाजीपुर के थाना सुहवल के अंतर्गत ग्राम सरैया में दिनांक 24 अक्टूबर को उच्च जाति के लोगों ने एक तरफा बिन्द समाज व बस्ती के उपर अंधाधुंध गोलियां चलाई जिसमें अपराधियों की गोलियों से धर्मेंद्र बिन्द लहुलूहान हो गए जो बीएचयू ट्रामा सेंटर में जीवन मौत से जूझ रहे हैं। अभी तक गोली चलाने वाले मुख्य अपराधी समेत आधा दर्जन से अधिक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है।

जिन प्रतिबंधित असलहों से गोली मारी गई/ फायरिंग किया गया है उन असलहों को अभी तक पुलिस जप्त नहीं कर पाई है। पुलिस का हाथ बंधा हुआ है कि सभी हमलावर उच्च जाति के लोग हैं. उनको सत्ता संरक्षण मिल रहा है।

एक जान लेवा हमला 13 अक्टूबर को गहमर में संतोष यादव और सर्वजीत यादव के उपर धारदार हथियारों से हुआ जिसमें स्थानीय पुलिस हमले उचित धारा न जोड़ कर हमलावरों को गिरफ्तार करने से पीछे हट रही है।

प्रदेश की आम जनता के लिए यह स्थिति बहुत खतरनाक है उनका रोज का जीवन डर के घेरे में है।

यह स्थिति तब है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराध के खिलाफ 'ज़ीरो टोलरेंस' का झूठा ढोल पीटते हैं और इस झूठ के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और देश-प्रदेश की मीडिया भी इस झूठ को बड़े जोर-शोर से प्रसारित करके माफियाओं के सबसे बड़े सरंक्षक मुख्यमंत्री को माफिया संहारक का खिताब दे रही है। प्रदेश की जनता इस विडम्बनापूर्ण स्थिति को देख रही और इससे मुक्ति के लिए छटपटा रही है। पिछले लोकसभा चुनावों में इस छटपटाहट की भी बड़ी भूमिका रही और प्रदेश की जनता ने सबको चौकातें हुए उत्तर प्रदेश से भाजपा को मजबूती से पीछे धकेला और विपक्ष पर भरोसा जताया।
विपक्ष पर जनता के इस भरोसे के साथ ही विपक्ष पर यह जिम्मेदारी भी आयद हुई कि वह प्रदेश में लूट-झूठ-दमन-हत्या-बलात्कार के सरकारी जंगलराज का प्रतिरोध करें, सड़कों पर उतरे और प्रदेश की बदहाली को लोकसभा में बड़े सवाल के तौर पर खड़ा करें। नौजवानों और आम जनता के प्रतिरोध के दम पर इस महिला व दलित विरोधी सत्ता को पीछे धकेलना होगा.

R.G. Kar Movement Continues

CHANDRASMITA CHOUDHURI

The movement demanding justice for the rape and murder at R.G. Kar Medical College has continued since August 9th. West Bengal has rarely seen such deep anger and emotion expressed by so many people in a rational, peaceful, and resolute protest in recent years. On August 14th, countless people across the state—from villages, towns, and cities—took to the streets to reclaim the night. In a short time, the R.G. Kar movement has stirred a massive section of society and exerted significant pressure on the government and state machinery, an occurrence rarely seen recently.

Rape and murder have, tragically, become everyday news in this country. Government statistics record a rape complaint every 16 minutes, but conviction rates are low. “What was she doing alone in the seminar room at that hour?”—this comment by then-principal Sandeep Ghosh following the R.G. Kar incident sparked a massive movement. Each incident that fosters or rewards a culture of violence against women incites public anger. In the case of R.G. Kar Medical College, this anger has erupted, reminiscent of the Nirbhaya case of 2012-13. Compounding this are concerns over doctors' safety, widespread dissatisfaction with corruption in medical education, and the healthcare system in general, along with the specific state of R.G. Kar College. Most significantly, repeated blunders by the state government, along with insensitive and irresponsible remarks from leaders, including the Chief Minister, have fueled public frustration.

The central demand of the movement is clear: "We Want Justice." Without this movement, the pursuit of justice would likely have been silenced. We are more accustomed to seeing justice silenced and people grieving in silence. Thus, the progress made in the judicial process so far is a victory for the movement. Whether the CBI investigation will fully reveal the truth, and whether the Supreme Court’s oversight will ensure appropriate punishment for the real culprits, remains uncertain. To date, the CBI has only placed a chargesheet against the sole accused, Sanjoy Roy, a Kolkata Police civic volunteer, without clarifying the entire incident. However, some action has been taken due to the pressure from this unprecedented mass movement. Recognizing the scale of the public outcry, the Supreme Court has taken up the case on its own initiative. There's no set rule for how large a protest will grow, nor is there a fixed formula for how the state (including the judiciary) will respond. However, the mood of the R.G. Kar movement makes it clear that the quest for justice will not be abandoned halfway.

The Supreme Court and the junior doctors’ movement have made doctors’ safety a crucial issue. Yet the question of women’s safety in workplaces has lost importance as the doctors' movement took center stage. Neither the Supreme Court, the state government, nor the junior doctors emphasized sexual harassment in workplaces during discussions. On August 14th, when women came out on the streets

their primary issues were unsafe nights and their daily experiences of harassment. The state government's conservative proposal to restrict women from night shifts as a safety measure was criticized by the Court. Similarly, the Aparajita Bill weakens the potential for genuine justice by focusing on swift, severe punishments, including the death penalty, rather than preventing rape and ensuring justice in every case. A decade after the Nirbhaya movement, the R.G. Kar movement has reignited the issues of women's safety and freedom, which must not be allowed to be trapped in legal formalities.

Through organized, united strength and determined protest, junior doctors have managed to make the state government retreat to some extent. After a 15-day fast, the government accepted most of their demands. However, the threat of corruption in the system has made doctors concerned about their future security. They have decided to continue their movement in other forms to demand safety. Equally important to doctors' safety is the need for a corruption-free education and examination system and assurance of accessible healthcare for the public. It is essential to end both the nest of corruption and the health business trap that weakens government systems by issuing health insurance cards to the public. If the ongoing junior doctors' movement can pave the way for a broader public health movement in Bengal, it will mark a victory for the junior doctors' movement.

The character of the R.G. Kar movement is civic. This movement has brought ordinary women from villages onto the streets, as well as people from various professions and generations across the state. No political party has been able to take the lead in this civic movement; the main opposition party, the BJP, has repeatedly tried to seize control but failed. The Chief Minister herself took to the streets, demanding the death penalty, while the opposition clamored for her resignation. However, the movement has remained steadfast in its demand for justice.

The last two elections in West Bengal showed that while people are deeply disillusioned with the state government, they are wary of the central ruling party in the main opposition position and are not inclined to bring it to power in the state. As a result, the Trinamool Congress has gained votes and seats in both the 2021 Assembly elections and recently held 2024 Lok Sabha elections. But this does not mean that people will forgive the government and ruling party for their glaring mistakes, corruption, and misgovernance. This is the primary message of the ongoing civic movement. Breaking the BJP-Trinamool polarization in Bengal, this movement serves as a foundation for the rise of a third bloc, grounded in left-liberal values. Despite the festive season's arrival, the enthusiasm for the movement shows no signs of waning. The movement has symbolized women icons, and images have become emblematic. Salil, Sukanta, and Hemanta are alive again in the air of Bengal. New songs have been created, and street paintings have also become an essential part of the movement. The struggle for reclaiming the night, changing the day, and securing rights continues—and will continue.

झारखंड विधानसभा चुनाव का नतीजा

अविनाश रंजन

झारखंडी युवाओं ने, विधानसभा चुनाव के नतीजों के जरिए बता दिया कि "नफरत नहीं रोजगार चाहिए, अस्मिता और स्थानीयता का अधिकार चाहिए"।

"घुसपैठियों की, हिन्दू विरोधी सरकार 20 नवंबर को गंगा में बहने वाली है।" भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का यह कथन भाजपा की राजनीति को, विधानसभा चुनाव में उनके एजेंडे को समग्रता में बयान करती है।

घुसपैठ, हिन्दू मुस्लिम, संथाली बांग्लादेशी, नफरत की राजनीति को, झारखंड के दो तिहाई नौजवान ने खारिज कर दिया है। Axis My India के एग्जिट पोल अनुसार 18–45 वर्ष के 67 प्रतिशत युवाओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। वहीं पचास प्रतिशत से अधिक नौजवानों ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया।

झारखंड में रोजगार सबसे प्रमुख सवाल रहा है, भाजपा की सरकार रोजगार के सवालों पर ही गई थी।

कोरोना महामारी के दौर में 15 मार्च 2021 को रोजगार के सवाल से परेशान होकर, झारखंड के हजारों नौजवान, आरवाईए के नेतृत्व में रांची की सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किए। "हेमंत सरकार वादा निभाओ रोजगार कहां है यह बतलाओ" का नारा राज्यभर के नौजवानों ने लगाया। 02 लाख 78 हजार सृजित पदों पर अविलंब नियुक्ति और बेरोजगारी भत्ता राज्य का मुख्य मुद्दा बना। जिसके बाद सरकार पर दबाव बढ़ा।

राज्य सरकार ने इसके बाद 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण को लेकर कानून बनाया। पर भाजपा ने राज्यपाल और केंद्र सरकार की मदद से इस पर रोक लगा दिया, जिससे झारखंड के युवा प्रभावित हुए।

इस दौर में अडानी को गोड्डा का पावर प्लांट देना, झारखंड के पुराने दंश को फिर से जिंदा किया है। विस्थापन, प्रदूषण, प्राकृतिक दोहन झारखंड के हिस्से और लाभ पूंजीपतियों के हिस्से। कॉरपोरेटीकरण और बेरोजगारी के इस सामंजस्य को झारखंडी युवाओं ने पिछले 24 सालों में बखूबी समझा है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है और प्रति व्यक्ति पलायन भी सबसे अधिक झारखंड में है। झारखंड आंदोलनकारी, महान मजदूर नेता कॉमरेड ऐ के रॉय ने झारखंड को लालखंड बनाने का विचार प्रस्तुत किया था, झारखंड के संसाधनों पर झारखंड की जनता का अधिकार का जो सपना देखा था, वो सपना आज झारखंड का नौजवान देखने लगा है।

झारखंड की सरकार ने 2.78 लाख रिक्त सरकारी पदों को अविलंब भरने और परीक्षा कैलेंडर जारी करने को प्राथमिकता में शामिल किया है। सरकार इन वादों को पूरा करने में देरी और बेमानी करती है तो नौजवानों का गुस्सा फूट पड़ेगा। झारखंड के युवा नफरत फैलाने वाली, बांटने वाली राजनीति को खारिज करते हैं और झारखंड के आंदोलन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, अपने अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए और झारखंड के समग्र विकास के लिए आंदोलन को तैयार हैं।

बदलो बिहार न्याय यात्रा: युवा चेतना की नई लहर और बिहार के पुनर्निर्माण का आह्वान

वतन कुमार

भाकपा (माले) लिबरेशन द्वारा बिहार के विभिन्न हिस्सों में आयोजित 'बदलो बिहार न्याय यात्रा' आज की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना बनकर उभरी है। यह अभियान न सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ बुलंद किया, बल्कि राज्य में न्यायपूर्ण और समतामूलक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य लेकर सैकड़ों किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी की । 16 से 25 अक्टूबर तक पांच मार्गों पर चली इस यात्रा ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों को एक साथ जोड़ते हुए उनके अधिकारों के संघर्ष को एक नई दिशा दी।

यात्रा का प्रारंभ नवादा से किया गया, जहां हाल ही में गरीबों के 32 घरों को जलाने की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस अन्याय के खिलाफ जनाक्रोश की लहर को देखते हुए माले ने इसे अन्याय के खिलाफ अपने संघर्ष का प्रतीक बनाया और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का. दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में यह यात्रा आगे बढ़ी। जिस तरह से यात्रा को लोगों का समर्थन मिला, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक अभियान नहीं, बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है, जिसमें न्याय, रोजगार और समानता की आवाज बुलंद हुई.

बिहार में पलायन और बेरोजगारी लंबे समय से एक गंभीर समस्या बने हुए हैं। राज्य के लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार के गांव और छोटे कस्बे रोजगार के अभाव में सूने होते जा रहे हैं। 'बदलो बिहार न्याय यात्रा' ने इस समस्या को गहराई से समझते हुए इसे अपने आंदोलन का मुख्य एजेंडा बनाया। बेरोजगारी के साथ-साथ निजीकरण की नीतियों ने भी युवाओं के रोजगार के अवसरों को सीमित कर दिया है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की घटती संख्या और निजी क्षेत्रों में सीमित अवसरों ने बिहार के युवाओं के भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। यह यात्रा इस संकट को उजागर करने के लिए एक मुखर माध्यम बनी है।

यात्रा में चल रहे इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफताब आलम, जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष धनंजय और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव एवं पालीगंज विधायक संदीप सौरव ने हर पड़ाव पर बिहार के युवाओं की समस्याओं पर केंद्रित सवालों से सत्ता को चुनौती दी। इन युवा नेताओं ने पलायन, बेरोजगारी और निजीकरण को लेकर सरकार पर करारा हमला बोलते हुए पूछा, "आखिर कब तक बिहार के नौजवान रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन को मजबूर रहेंगे? क्यों हमारे नौजवानों को अपने घर-गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में छोटे-मोटे कामों के लिए संघर्ष करना पड़ता है? कहा कि सत्ता पक्ष की नीतियां ही बिहार में रोजगार संकट का मुख्य कारण हैं। सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की घटती संख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और गहराया है, जिससे युवाओं के लिए आजीविका का सवाल पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गया है। यह सरकार जानबूझकर सरकारी नौकरियों के अवसरों को सीमित कर रही है, ताकि निजीकरण की नीति को बढ़ावा दिया जा सके।

निजीकरण से लाभ केवल पूंजीपतियों को हो रहा है, जबकि इसके दुष्परिणाम बिहार के युवाओं को भुगतने पड़ रहे हैं। “यह सरकार विकास के नाम पर केवल धनी वर्ग को फायदा पहुंचा रही है। बिहार के साधारण युवक, जो अपनी मेहनत और लगन के दम पर रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें यह सरकार मजबूरी और बेबसी की ओर धकेल रही है। आज बिहार के युवाओं के पास न तो रोजगार की गारंटी है और न ही सम्मानजनक जीवन की आशा।

बिहार के गांव-कस्बे रोजगार के अभाव में वीरान हो रहे हैं। यहां के नौजवानों को महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में जाकर रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आखिर यह कैसा विकास है, जिसमें राज्य के युवाओं को सम्मानजनक जीवन की जगह परायों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है? अगर सत्ता पक्ष वास्तव में विकास के प्रति ईमानदार है, तो उसे बिहार के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रोजगार के ठोस अवसर पैदा करने होंगे।

यह सवाल आज बिहार के नौजवानों की पीड़ा का प्रतिबिंब बन गया है, और माले ने इसे न्याय यात्रा के माध्यम से एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में उठाया है। राज्य में सरकारी नौकरियों की संख्या को बढ़ाने और निजीकरण की नीतियों को रोकने से ही इस समस्या का समाधान संभव है।

इस यात्रा की सबसे खास बात रही नौजवानों की उत्साहजनक भागीदारी। हर जिले, हर कस्बे और हर गांव से युवाओं ने इस यात्रा में शामिल होकर अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई। उनके नारों और जोश से यह साफ झलकता रहा कि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में 'बदलो बिहार न्याय सम्मेलन' के साथ यात्रा का समापन हुआ। यहां यात्रा के पांचों मार्गों से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और राज्य में न्याय, रोजगार और समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस सम्मेलन ने न्याय यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों को एक संगठित और ठोस दिशा देने का कार्य किया। सम्मेलन में लोगों ने बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा करने का संकल्प लिया, जो कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति को नई दिशा देने की क्षमता रखता है।

'बदलो बिहार न्याय यात्रा' ने राज्य के युवाओं को उनके अधिकारों और उनके भविष्य के प्रति जागरूक किया है। इस यात्रा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि एक न्यायपूर्ण और समतामूलक बिहार का निर्माण तभी संभव है जब राज्य के लोग, खासकर नौजवान, संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें।

इस यात्रा ने बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई चेतना का संचार किया है। यह यात्रा एक संकेत है कि अगर राज्य में सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, पलायन और निजीकरण के मुद्दों पर सार्थक समाधान नहीं ढूंढे गए, तो यह जन आंदोलन आने वाले दिनों में और भी व्यापक रूप ले सकता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस, आरओ-एआरओ परीक्षा के खिलाफ आंदोलन

सुनील मौर्या

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस, आरओ-एआरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन और अलग - अलग शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ 11 नवंबर को शुरू हुआ आंदोलन सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई विगत परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने प्रदेश में बड़े सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं के कारण पीसीएस परीक्षा को टालना पड़ा और आरओ-एआरओ परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा।

अब जब लंबे समय बाद यह परीक्षा आयोजित की जा रही थी, तब आयोग ने मनमाने तरीके से दो अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपना कर मूल्यांकन होना था। इस फैसले को लेकर छात्रों में गहरा असंतोष और अविश्वास फैल गया। जिसको लेकर हजारों की संख्या में छात्र-युवाओं का हुजूम लोक सेवा आयोग के गेट के समक्ष इकट्ठा होकर इस मनमाने फैसले को वापस लेने और परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की मांग करने लगा।

Uयह आंदोलन केवल नॉर्मलाइजेशन और शिफ्टों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, नौजवानों के रोजगार के अधिकार और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवानों के 5 दिनों तक चले आंदोलन के आगे तानाशाह योगी सरकार को झुकना पड़ा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली पीसीएस तथा RO, ARO की परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने तथा नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर चल रहे नौजवानों के आंदोलन की जीत हुई। नौजवानों के इस आंदोलन को योगी सरकार द्वारा दमन करने की भरपूर कोशिश की गई तथा आंदोलन कर रहे नौजवानों पर जबरन लाठी बरसाने से लेकर जेल भेजने तक की कार्रवाई की गई।

प्रदेश में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं जिनको भरकर नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उन सारे पदों को बिना भरे नौजवानों पर सिर्फ लाठी बरसाने का काम कर रही है। इस सरकार में एक भी परीक्षा का संचालन व्यवस्थित तरीके से नहीं कराया गया है।सभी परीक्षाओं में धांधली, भ्रष्टाचार, पेपर लीक इत्यादि के आरोप लगते रहे हैं और सरकार को परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा कराना पड़ा है।

यह भी बहुत जाहिर है कि पहले तो सरकार अपने सभी विफलताओं को छुपाने की कोशिश करती है लेकिन उसके खिलाफ जब छात्र-नौजवान सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं तो अंततः सरकार को आंदोलन के दबाव में आकर उनकी बात माननी पड़ती है। इससे यह साफ पता चलता है कि छात्र-नौजवानों को अपने रोजगार का अधिकार भी सरकार से लड़कर हासिल करना होगा।

योगी सरकार की नीतियाँ रोजगार विरोधी रही है। अगर सरकार ने खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द नहीं भरा और सम्मानजनक रोजगार के अन्य अवसर नहीं उपलब्ध कराए गए तो रोजगार के मूलभूत अधिकार के लिए नौजवान एक बार फिर से सड़कों पर आएंगे और योगी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इस आंदोलन में इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवानों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और नौजवानों का हौसला बढ़ाने के साथ-साथ आंदोलन को मजबूत बनाने में पूरी भूमिका अदा की है।

पूंजीपतियों और सांप्रदायिक ताकतों द्वारा देश पर थोपी जा रही तबाही

वतन कुमार

इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) ने बेगूसराय के हरदिया में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में नौजवानों की भूमिका विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया। इस मंच पर केंद्र और राज्य सरकार की युवा-विरोधी, जन-विरोधी और पूंजीवादी नीतियों का गहन विश्लेषण और तीखी आलोचना हुई। कार्यक्रम में आरवाईए के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में पूंजीवाद और सांप्रदायिकता के खतरनाक गठजोड़ को उजागर किया।

नीरज कुमार ने कहा, मोदी सरकार की नीतियां देश के युवाओं, मजदूरों और किसानों को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल रही हैं। सार्वजनिक संसाधनों और संस्थानों का निजीकरण अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का षंड्यत्र है। बंद हो रहे कल-कारखाने, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच यह सरकार कॉरपोरेट घरानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। 'सबका साथ, सबका विकास' जैसे नारे सिर्फ छलावा हैं। हकीकत यह है कि यह सरकार सांप्रदायिकता और पूंजीवाद के गठजोड़ के सहारे देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को कमजोर कर रही है।

उन्होंने निजीकरण को आर्थिक लूट का संगठित षंड्यत्र बताते हुए कहा कि बंद पड़े सार्वजनिक उपक्रम और संस्थान, जो लाखों लोगों के रोजगार का आधार थे, अब सस्ते दामों पर कॉरपोरेट घरानों को सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल आर्थिक नीतियों का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार की 'कॉरपोरेटपरस्ती' और युवा विरोधी मानसिकता का खुला प्रमाण है।

जो सरकार रोजगार देने के बजाय युवाओं को सांप्रदायिक नफरत और धार्मिक उन्माद में फंसा रही है, वह असल में सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के मूल्यों पर हमला कर रही है। यह सरकार चाहती है कि युवा सवाल न करें, बल्कि एक अंधभक्त की भूमिका निभाएं।

भाजपा-आरएसएस की राजनीति का एकमात्र उद्देश्य सत्ता बनाए रखना है, और इसके लिए वे समाज को विभाजित करने का खेल खेल रहे हैं। युवाओं के हाथों में किताबों, कलम और काम की जगह तलवारें थमाई जा रही हैं। मस्जिदों और मुसलमान बस्तियों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने का अभियान चलाया जा रहा है।

सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए धर्म और इतिहास को हथियार बनाया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि उनका असली दुश्मन वह व्यक्ति है जो दूसरे धर्म को मानता है। जबकि असली दुश्मन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और कमजोर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली है।

इस राजनीति के गंभीर परिणाम हो रहे हैं। समाज में हिंसा बढ़ रही है, समुदायों के बीच दरार गहरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि युवा अपनी ऊर्जा और संभावनाओं को नफरत के रास्ते में बर्बाद कर रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होने वाले अधिकतर युवा बेरोजगार होते हैं। उन्हें रोजगार न देकर नफरत के हथियार में बदला जा रहा है। हमें संगठित होकर इस षंड्यत्र को बेनकाब करना होगा।

आरवाईए के राज्य सह सचिव वतन कुमार ने कहा कि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है, जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा युवाओं से बना है। ये युवा न केवल देश का वर्तमान हैं, बल्कि भविष्य भी हैं। शिक्षा प्राप्त करके, हुनर विकसित करके और रोजगार पाकर ये युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। लेकिन जब ये युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं,पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सरकारी नौकरियों की संख्या घट रही है, जबकि निजी क्षेत्र में भी अवसर सीमित हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल इंडिया जैसे बड़े-बड़े नारों के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही है। रोजगार सृजन के बजाय उद्योग-धंधे बंद हो रहे हैं, और छोटे व्यापार जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियों के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं।

इसलिए नौजवानों को यह समझाना होगा कि उनकी असली लड़ाई बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, न कि उनके पड़ोसी के धर्म के खिलाफ। आज युवाओं के हाथों को तलवारें नहीं,बल्कि नौकरियां और अवसर चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिक नफरत का शिकार बनाने की कोशिश उनके भविष्य को अंधकारमय करने की साजिश है। हमें एकजुट होकर इस राजनीति का विरोध करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि भारत का युवा नफरत के नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा और विकास के रास्ते पर चले।

संभल हत्याकांड और अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आरवाईए का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

वतन कुमार

संभल हत्याकांड के न्यायिक जांच, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, और अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग को लेकर इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर देश के अलग-अलग हिस्सों में हुआ प्रदर्शन।

बिहार के बेगूसराय में आयोजित प्रतिरोध मार्च को संबोधित करते हुए आरवाईए के राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि आज हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। देश की सामाजिक एकता, लोकतांत्रिक मूल्य, और संवैधानिक संस्थाओं पर आज अभूतपूर्व हमले हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जनविरोधी और सांप्रदायिक राजनीति का ऐसा घिनौना मॉडल पेश किया है, जो न केवल हमारे समाज को बांट रहा है, बल्कि हमारे लोकतंत्र और संविधान की नींव को कमजोर कर रहा है। यह सरकार पूंजीपतियों की गुलामी और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति का खतरनाक मेल बन चुकी है।

संभल की घटना इसका ताजा उदाहरण है। निहत्थे नागरिकों पर पुलिस की बर्बरता, पांच मासूम नौजवानों की गोली मारकर हत्या, और उसके बाद सरकार की खामोशी ने यह साफ कर दिया है कि यह सरकार न केवल क्रूर है, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारियों से भी पूरी तरह भाग रही है। जब पुलिस, जिसे जनता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, वही

जनता पर गोलियां चलाती है और निर्दोषों की जान लेती है, तो यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन और हमारे संविधान पर सीधा हमला है।

सरकार की चुप्पी और दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई न करना यह साबित करता है कि यह सरकार कानून के राज को नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक एजेंडे को थोपने में विश्वास करती है।

लेकिन यह केवल सांप्रदायिक हिंसा की बात नहीं है। यह उस बड़े खेल का हिस्सा है, जहां देश की संपत्तियां और लोकतंत्र कुछ पूंजीपतियों के हाथों में बेची जा रही हैं। अडानी का मामला इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। अमेरिका में अडानी पर भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपये की रिश्वत देने के गंभीर आरोप लगे हैं। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। यह घोटाला दिखाता है कि मोदी सरकार कैसे अपने पूंजीपति मित्रों के लिए देश की संस्थाओं और संसाधनों को गिरवी रख चुकी है।

देश के संसद में अडानी का नाम तक लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है। विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, यह कैसा लोकतंत्र है, जहां संसद को भी पूंजीपतियों के हित में बंधक बना दिया गया है?

अडानी को मोदी सरकार का संरक्षण स्पष्ट है। चाहे बंदरगाहों का निजीकरण हो, कोयला खदानों का आवंटन हो, या सौर ऊर्जा के बड़े प्रोजेक्ट—हर जगह अडानी को ही फायदा पहुंचाया गया है। जबकि आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, और गरीबी से जूझ रही है, यह सरकार अडानी जैसे पूंजीपतियों की जेबें भरने में व्यस्त है।

जब-जब सरकार पर घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तब-तब वह सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। संभल की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पुलिस की बर्बरता और सांप्रदायिक हिंसा केवल जनता को असली मुद्दों से दूर रखने का षंड्यत्र है।

यह सरकार समाज को बांटकर अपने पूंजीपति मित्रों के अपराध छुपाने का प्रयास करती है। संभल जैसे मामले केवल सांप्रदायिक तनाव नहीं, बल्कि जनता की असल समस्याओं—महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली—से ध्यान हटाने के लिए बनाए गए मुद्दे हैं।

हम साफ देख सकते हैं कि मोदी सरकार और अडानी का गठजोड़ देश के लिए कितना खतरनाक है। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि हमारे संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक ताने-बाने पर सीधा हमला है। मोदी सरकार अडानी जैसे पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए देश की जनता को धोखा दे रही है।

मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन को संबोधित करते हुए आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आफताब आलम ने कहा कि जब जनता के मुद्दों को संसद में उठाने पर रोक लगाई जाती है, जब सत्य को दबाने के लिए मीडिया को खरीद लिया जाता है, पीड़ितों से मिलने की कोशिश करने पर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, जब कानून व्यवस्था का इस्तेमाल विरोधियों को कुचलने के लिए किया जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि यह सरकार लोकतंत्र नहीं, बल्कि तानाशाही की ओर बढ़ रही है।

यह लड़ाई केवल अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, संविधान, और सामाजिक एकता की रक्षा के लिए है। यह लड़ाई पूंजीवादी लूट और सांप्रदायिक नफरत की राजनीति के खिलाफ है।

हमें एक नई आजादी की जरूरत है—एक ऐसी आजादी जो इस पूंजीवादी-सांप्रदायिक गठजोड़ से मुक्त हो। एक ऐसी आजादी जो समाज के हर तबके को समान अवसर और न्याय दे सके।

हम इंकलाबी नौजवान सभा की ओर से देश के हर नौजवान से आह्वान करते हैं—उठो, संगठित हो, और इस अन्याय व अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाओ। यह समय का तकाजा है। यह हमारी जिम्मेदारी है। और यह हमारी इंकलाब की पुकार है।

Published by Revolutionary Youth Association

एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न
रोटी खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता
है
मैं पूछता हूँ--
'यह तीसरा आदमी कौन
है ?'
मेरे देश की संसद मौन
है।

- धूमिल

Email: ryahqofficial@gmail.com
ADDRESS: CHARU BHAWAN, U-90, SHAKARPUR, DELHI 110092
RYAindia RYAindia_official RYA
WWW.RYAINDIA.NET